(च) क्योंकि राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में पुस्तकों और विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखने का निश्चय ही एक बड़ा भाग है, इस लिये इस दिशा में अनेक कदम उठाए गये हैं और इससे सम्बन्धित प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं :

(1) भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में प्रत्येक की उत्कृष्ट लोकप्रिय 10 पुस्तकों तक को अनुदित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्याय को धन उपलब्ध किया गया है, ताकि सारे देश के लिए सामान्य पुस्तकों का एक ऐसा सेट तैयार हो जाए, जिसे देश के लोग पढ़ सकें तथा देश के विभिन्न भागों में प्रचलित संस्कृतियों, सामाजिक रिवाजों, प्रथाओं और रहन-सहन के ढंग के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसी पुस्तकों की माला को "आदान प्रदान" कहा जाएगा।

(2) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, "अखिल भारतीय स्तर के प्रमुख व्यक्तियों का राष्ट्रीय जीवन वृत्त" से संबंधित पुस्तकों के सस्ते संस्करण निकाल रहा है।

(3) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को, कुछ महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों के विश्वविद्यालय स्तर के स्रोत ग्रंथ निर्माण करने का कार्य भी सौंपा गया है ताकि ऐसी कुछ सामान्य पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, जो विश्वविद्यालय स्तर पर, सभी भारतीय विद्यार्थियों को संदर्भ साहित्य उपलब्ध हो सके।

(4) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को, ऐसी 100 पुस्तकें तैयार करने का भी कार्य सौंपा गया है, जो स्कूली सभी बच्चों के लिये अनुपूरक रीडरों के रूप में प्रयुक्त हो सके। यह पुस्तक माला "नेहरू पुस्तकालय पुस्तकें" कहलायेगी। प्रत्येक पुस्तकों के विषय को इस बातका ध्यान रखकर चुना जाएगा कि वह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में कितना महत्वपूर्ण होगा तथा देश में फूट डालने वाली प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेदार अज्ञानता, अन्धविश्वास तथा पूर्वाग्रहों को दूर करने में कितना सहायक सिद्ध होगा।

(छ) सरकार का चार प्रादेशिक भाषा संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिन के अधीन हिन्दी क्षेत्रों में भाषा-अध्यापकों को अपने विद्यार्थियों को दक्षिण भारत की भाषाएं तथा हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसी प्रकार, अहिन्दी भाषी राज्यों के भाषा अध्यापकों को भी अपने विद्यार्थियों को हिन्दी तथा अन्य गैर-प्रादेशिक भाषाएं पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। यथा सम्भव अधिक से अधिक नागरिकों को बहुभाषी बनाने का प्रयत्न है, जिसके फलस्वरूप अच्छी सद्भावना उत्पन्न होगी और इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी।

विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों का निष्कासन

844. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री प० मु० सईद :
श्री भा० सुन्दर लाल :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आपत्तिजनक गति-

विधियों के कारण कितने विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों का सरकार ने भारत से निष्कासन किया है; और

(ख) इस प्रकार की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):(क) पत्नियों के अलावा दस ।

(ख) एक को विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के लिए तथा अन्य नौ को अवांछनीय समझी जाने वाली गतिविधियों के लिए । उनके ब्यौरे प्रकट करना लोक-हित में नहीं होगा ।

Seminar on Criminal Law and Contemporary Social changes

845. SHRI DHIRESWAR KALITA :
SHRI D.N. PATODIA :
SHRI LATAFAT ALI KHAN :
SHRI P.C. ADICHAN :
DR. RANEN SEN :
SHRI INDRAJIT GUPTA :
SHRI MUHAMMAD SHERIFF :
SHRI K P. SINGH DEO :
SHRI GADILIGANA GOWD :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the subjcet discussed at the Seminar on Criminal Law and Contemporary Social Changes held recently in New Delhi ;

(b) the recommendation made by the Seminar on those subjects ; and

(c) Government's reaction thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The following specific subjects were discussed at the Seminar :

(i) Compensation for the Victims of Crime ;

(ii) Crime and Punishment ;

(iii) Working of the separate of the judiciary from the executive ; and

(iv) Reforms in Criminal Law and its administration relating to prevention and investigation of crime and prosecution of offenders.

(b) The following are some of the broad recommendations made by the Seminar :

(i) Some measures must be adopted whereby the victims of crime are paid compensation for the loss suffered by them ;

(ii) Greater stress should be laid on correctional measures in handling convicted offenders especially children and adolescents ;

(iii) Awarding deterrent sentences on 'white collar' criminals ;

(iv) Amending the existing laws to bring about uniformity in the pattern of separation of the judiciary from the executive in all the States.

(c) The various recommendations made by the Seminar will be examined by the Government on receipt of its Report.

C.S.I.S. Appointments

846. SHRI SRADAKAR SUPAKAR : Will the Ministers of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state :

(a) whether a special Committee to look into the appointments in the Council of Scientific and Industrial Research has been appointed recently ; and

(b) if so, the names of the members of the Committee ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V.K.R.V. RAO) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.